[Shri C. K. Jaffer Sharief]

up a big empire. We are trying to see whether reputed caterers or ITDC people will come. I am taking this opportunity to make it very clear that nobody should try to attribute motives to us. We have to select people depending upon the requirements. If there s an area where bulk feeding comes to cater to a number of people, then, there should be a man who has the ability to invest and organise such a network and accept the responsibility. If there is a small area of feeding, we need not give to anybody. We can give it to our unemployed youth on a voluntary basis so that they can earn their livelihood. So this is what broadly we have in our mind. We are trying our best to improve it. I am sure we will be able to achieve tangible results.

One hon friend complained that he wrote to me but did not get any response. I am surprised to hear this from him because I for one do not have any other work except signing only reply letters to the Members of Parliament.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: I do not know whether that letter has reached your hands. I did not get any response.

SHRI C. K. JAFFAR SHARIEF: Certainly I will look into that.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: He did not write to you... (*Interruptions*)...

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: About two or a year ago, I wrote a letter to you but there was no response. Then about two or three months ago..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Two years ago he was not the Railway Minister.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: I know that he was then a Minister.. (*Interruptions*)...

SHRI C. K. JAFFAR SHARIEF: One of the problems I am facing is I am not finding time to apply my mind to the kind of vision that it requires. The basic vision of the Railways should be to develop its network keeping in mind the future, industrial development of the country so that the country can prosper. Nevertheless it will be my endeavour not only to acknowledge the letters but also to give replies to the letters of the Members Every day not 50 or 60 letters but hundreds of letters come to us and we keep on writing to every one of them. We have been doing it. If there are any lapses on our part we will try to correct them. I appeal to the Member not to confine their criticism just to the catering area but if they find any other area where improvements are needed we will welcome your suggestions and we will give the utmost attention and seriousness to the suggestions given by you.

Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Now, the hon. Textiles Minister to make a statement.

STATEMENT BY MINISTER

Revival of National Textile Corporation and British India Corporation

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी,

नेशनल टैक्सटाईल कारपोरेशन तथा ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन की बिगड़ती आर्थिक स्थिति के बारे में समय-समय पर माननीय सदस्यों ने अपनी चिंता व्यक्त की है तथा इस बात पर बल दिया है कि इन उपक्रमों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये कुछ कारगर कदम उठाये जायें । दोनों उपक्रमों में स्थिति अत्यधिक गंभीर हो गई है। एन०टी०सी० में कुल घाटा बढ़कर 2300 करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच गया है जबकि बी०आई० सी० की दो सूती मिलों में घाटा 155 करोड़ रुपये के लगभग हो गया है। इस संदर्भ में यह आवश्यक हो जाता

है कि इस प्रवृत्ति को रोका जाय नहीं तो वह समय दूर नहीं जबकि ये उपक्रम बन्द होने की स्थिति में आ जायेंगे और लगभग 1 लाख 70 हजार इससे जुड़े हुये कर्मचारी एवं मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे ।

इस संदर्भ में उपक्रमों के लिए एक बेहतर भविष्य की आशा करते हुए केन्द्र सरकार ने इस उपक्रमों को पुर्नजीवित करने की योजना को अनुमोदित किया है । इस योजना के मुख्य आधार हैं चुने हुए क्षेत्रों में आधुनिकीकरण, वित्तीय एवं प्रबंधकीय प्रणाली में सुधार तथा धनराशि का प्रावधान जिससे कर्मचारी एवं मजदूर स्वैच्छिक रूप से सेवा निवृत्ति का विकास अपना सकें । स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना को उन मिलों के अधिकारियों कर्मचारियों, तथा श्रमिकों पर भी लागू किया जाएगा जिन मिलों की आर्थिक स्थिति में सुधार आने की अब कोई संभावना नहीं है जिन्हे बन्द करना पड़ेगा अथवा साथ की इकाई के साथ जोड़ना पड़ेगा ताकि उनका पुनरुद्धार किया जाए ।

एन० टी० सी० के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 532 करोड़ रुपये का आधुनिकीकरण के लिए प्रावधान किया गया है जिसका अधिकांश भाग वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा । 200 करोड़ रुपये इस संस्थान को अंतरिम सहायता के रूप में दिए जाएगें जिससे कि उपक्रम के पुनरुद्धार योजना के परिणाम आने तक यह संस्थान अपना काम चला सकें । स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अंतर्गत लगभग 79 हजार अधिकारी, कर्मचारी एवं मजदूरों के लिए 689 करोड़ रुपये की धनराशि का अगले 3 वर्षों के लिए प्रावधान किया गया है । यह धनराशि नेशनल रिन्यूअल फण्ड के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी । स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना एन०टी० सी० में 1988 से लागू है इसमें 1700 के करीब अधिकारी ही कर्मचारी एवं मजदूर लाभान्वित हो चुके हैं तथा अभी भी अपनाने के लिए बड़ी संख्या में इच्छुक हैं । धन के अभाव के कारण हम अभी इस योजना को अधिक कारगर रूप से चला नहीं पा रहे थे ।

बी० आई० सी० की सूती मिलों के लिए भी आठवीं पचवर्षीय योजना के दौरान 29 करोड़ रुपये का आधुनिकीकरण के लिए प्रावधान किया गया है इसके साथ ही 44 करोड़ रुपये अतरिम सहायता के रूप में तथा 79 करोड़ रुपये स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति, योजना के लिए रखे गए हैं जिससे कि लगभग 6700 अधिकारी, कर्मचारी एवं मजदूर लाभ उठ सकेंगे ।

इस पूरी पुनरुद्धार योजना का एक महत्वपूर्ण अंग पुनर्वास फण्ड की स्थापना है यह फण्ड जिसकी राशि 50 करोड़ रुपये रखी गई है उन मजदूरों को फिर से नए सिरे से नए रोजगारों में स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण आदि की सुविधाए प्रदान करेगी ।

सरकार ने सिद्धान्त रूप से यह भी निर्णय लिया है कि कुछ मिलों की परिस्थितियों को देखते हुए सरकार उसमें अपने पूंजी निवेश को कम करे । इन मिलों का चयन उचित समय पर किया जाएगा । इस निर्णय को कार्यान्वित करने की गति, समय व प्रक्रिया के विषय में कालान्तर निर्णय लिया जाएगा ।

मुझे पूर्ण विश्वास हैं कि माननीय सदस्यों तथा हमारे मजदूर संगठनों एवं कामगार भाईयों एवं अन्य संबधित सभी पक्षों की सहायता और सहयोग से हम इन रुग्ण उपक्रमों को एक स्वस्थ्य और लाभकारी इकाईयों में परिवर्तित कर सकेंगे ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Hon. Members, in view of the short time available at our disposal, I request you to be brief. Shri John Fernandes.

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): Sir, it is a very lengthy statement. I think more time should have been given to us to go through the statement. All the same, I want some clarifications form the hon. Minister.

These public sector undertakings were started a few decades back. It is obvious that their machinery will be obsolete now

[Shri John F. Fernandes]

when we are marching towards the most modern computer technology. I want to know from the hon. Minister whether, to revitalise these institutions, he will be going in for the most modern equipment as, otherwise, working on the obsolete machines, I do not think we can revitalise these undertakings. The losses made by this corporation are exorbitant. It will be futile to pump in more and more money to salvage this institution. I would like to know whether the Minister is contemplating winding up this institution rather than making it a white elephant.

चौधरी हरि सिंह (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन की बिगड़ती हुई आर्थिक अवस्था के संबंध में यह स्टेटमेंट मंत्री महोदय ने दिया है। देर से चेते, चेते जरूर लेकिन भारी नुकसान और घाटे के साथ। माननीय मंत्री जी ने इस में कहा है कि हम मजदूरों को काम और जो कारपोरेशन है उसकी स्थिति हम सुधारेंगे। तो सुधारने की डिटेल्स क्या हैं और इस घाटे को कम करने के लिए या पूरा करने के लिए तफसील के साथ आपके पास क्या योजना है यह मैं जानना चाहता हूं।

साथ ही साथ मैं समझता हूं हर सूबे के अंदर, हर राज्य के अंदर कोई न कोई दुकान, शोरूम होती है। साल भर में उनकी जितनी आमदनी नहीं होती, बिक्री नहीं होती उससे ज्यादा उस दुकान का किराया होता है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो अनइकोनोमिक हमारे शोरूम हैं सब स्टेट्स के अंदर उनको बंद करने का आप विचार करेंगे या नहीं या उनको सामान बढ़ा देने के लिए कहेंगे ?

तीसरे इसमें भारी संख्या में मजदूरों की छटनी का सवाल आयेगा उस छटनी को खत्म करने के लिए कौन सी नई योजना आप अपने व्यवहार में लायेंगे जिससे मजदूरों की अगर छटनी होगी तो उनको कहीं पर रोजगार मिल सके। इसके साथ ही आपका जो टेक्सटाइल कारपोरेशन है उसमें समय के साथ जो प्रोग्रेस होनी चाहिए वह नहीं होती है। आपका टेक्सटाइल कारपोरेशन, जो माडर्नाइजेशन होता है उसमें बहुत पिछड़ा रहता है। मैंने सवाल के जरिये भी पूछा था सिल्क में खासतौर से कि जापान की जो मशीनें हैं जिससे चमक आती है उससे सिल्क के दाम भी ज्यादा मिल सकते हैं तो वह क्यों नहीं मंगाते। कारपोरेशन का जो कपड़ा बनता है उनमें चमक नहीं होती, डिजाइन नहीं होता, लेटेस्ट डिजाइन नहीं होता, उनका मेटीरियल घटिया होता है। इन सब चीजों को माडर्नाइज करने के लिए, प्रोडेक्शन में सुधार लाने के लिए क्या एक्सपर्ट्स की सलाह लेंगे जिनकी एक्सपर्ट राय से कारपोरेशन को अच्छी क्वालिटी का कपड़ा मिल सके और कारपोरेशन की बिगड़ती हालत सुधर सके ?

श्रीमती सत्या बहिन (उत्तर प्रदेश) माननीय उपसभाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो ब्यान दिया है वास्तव में बड़ी चिंताजनक बात है। सरकार ने जब एन० टी० सी० की स्थापना की थी तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से नहीं की थी बल्कि जन कल्याण की भावना से और गरीब आदमियों के लिए सस्ता कपड़ा उपलब्ध कराने की भावना से की थी। मैं यह जानना चाहती हूं कि आज जो एन० टी० सी० की हालत हो गई है उसको जो बंद करने की नौबत आ गई है तो इसको कैसे ठीक किया जाएगा ? दूसरे कितनी मिलों का आधुनिकीकरण किया जायेगा और एडवांस टेक्नोलोजी जो दुनिया में विकसित है उसको अपनाने के लिए क्या कर रहे हैं ? मैं यह भी जानना चाहती हूं कि क्या किन्हीं मजदूर संगठनों ने यह ऑफर किया है कि पला-फलां मिल जो घाटे में चल रही है उसको हम चलायेंगे ? अगर कोई ऑफर आई है तो क्या आप उन्हें देंगे ?

मैं यह भी जानना चाहती हूं कि जहां तक एन० टी०सी० का सवाल है और जैसा माननीय हरि सिंह जी ने कहा कि एन० टी० सी० के जितने बड़े शोरूम हैं जितना उनको लाभ नहीं होता उससे ज्यादा खर्चा उनका होता है। इसके साथ ही मैं यह जोड़ना चाहती हूं कि जो एन० टी० सी० के अधिकारी हैं उनके दौरों पर, उनके रहन-सहन पर कितना खर्चा आता है और इस खर्चे पर मंत्री महोदय कोई अंकुश लगायेंगे या नहीं ? तीसरे जो लोग बेरोजगार हो जायेंगे उनको रोजगार देने के लिये कोन सी व्यवस्था आपने की है धन्यवाद।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Sir, this is not a modernisation plan. This is a retrenchment plan. This Minister, Mr. Ashok Gehlot, had been working very labouriously, secretly** the private sector for a very long time, and the whole intention is to hand over the entire textiles industry to the private sector.

He has allotted Rs. 532 crores for modernisation and he has allotted Rs. 884 crores for retrenchment. There are 120 mills in the country. The NTC was set up to poduce low-price textiles for the poor people of the country. That was the political commitment of the Government. That was the election manifesto. But thsi is a violation of the Congress election manifesto. This is a violation of the pledge that the Government has given to the people. This is a violation of the principles of a welfare State. We don't like to participate in putting questions to the Minister because** to the private sector. We all walk out now . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Mohammed Amin.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA** to the private sector. We are all walking out now.

(At this stage the hon. Member left the Chamber.)

AN HON. MEMBERS: Sir, no other Member is walking out.

(Interruptions) . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Nobody is walking out. . . *(Interruptions)* Let him go. Let him go. . . . *(interruptions)* . . . Let him walk out. Nobody is supporting him. Only he has walked out.

SHRI J. P. MATHUR: *

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Nothing will go on record. I am not permitting you. . . *(Interruption)* . . . Mr. Mathur, you are a very senior Member. Pou can't stand up and talk . . . *(interruption)* . . . No, I have not permitted you. You are a senior Member. Every time you stand up and interrupt. You don't want to follow the rules. . . . *(Interruption)* . . . Please sit down. Please I have not permitted you. Please sit down. I have not permitted you. Please sit down. Mohammed Amin. I have called him Mr. Amin, if you want to speak, you speak; otherwise, I will call the next

श्री मोहम्मद अमीन (पश्चिमी बंगाल) : मैं यह कहना चाहता हूं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिस क्राइसेस में फंसी हुई है उससे निकलने का कोई इंतकाम इस बयान के अन्दर नजर नहीं आ रहा है । पश्चिमी बंगाल में जो एन०टी०सी० की मिलें हैं उनमें मजदूरों की तनख्वाह तक बंद हो गई है । अब यह जो 532 करोड़ रुपये खर्च करने का हिसाब दिया गया है उससे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि इससे संकट से कहां तक निकाला जा सकेगा । इसलिए जब तक पालिसी में बुनियादी तौर पर कोई बदलाव नहीं आता है तब तक यह टैक्सटाइल इंडस्ट्री **(व्यवधान)**

شری محمد امین (مغربی بنگال): میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری جس کرائسس میں پھنسی ہوئی ہے اس سے نکلنے کا کوئی انتظام اس بیان کے اندر نظر نہیں آ رہا ہے۔ مغربی بنگال میں جو این۔ ٹی۔ سی۔ کی ملیں ہیں ان میں مزدوروں کی تنخواہ تک بند ہو گئی ہے اب یہ جو ۵۳۲ کروڑ روپیہ خرچ کرنے کا حساب دیا گیا ہے اس سے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اس سے سنکٹ سے کہاں تک نکالا جا سکے گا۔ اس لیے جب تک پالیسی میں بنیادی طور پر کوئی بدلاؤ نہیں آتا ہے تب تک یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ..."

مداخلت...

**Expunged as ordered by the Chair.
*Not recorded.

+[ ] Transliteration in Arabic Script.

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) आप क्लेरिफिकेशन पूछिये ।

श्री मोहम्मद अमीन: क्लेरिफिकेशन ही पूछ रहा हूं । जिन मजदूरों की तनख्वाह बंद हो गई है उनको तनख्वाह देने का इंतजाम नहीं है और इस स्टेटमेंट में भी इस बारे में कुछ नजर नहीं आता है । मेरी आखिरी बात यह है कि इससे मसीबत और बढेगी, मजदूरों की छटनी होगी । हम लोग इसका समर्थ नहीं कर सकते है ।

فری محمد امین : کلیری فیکیشن
ہی پوچھ رہا ہوں۔ جن مزدوروں کی
تنخواہ بند ہوگئی ہے انکو تنخواہ دینے کا
انتظام نہیں ہے اور اس اسٹیٹمنٹ میں بھی
اس بارے میں کچھ نظر نہیں آتا ہے میری
آخری بات یہ ہے کہ اس سے مصیبت
اور بڑھے گی۔ مزدوروں کی چھٹنی ہوگی
ہم لوگ اس کا سمرتھن نہیں کر سکتے ہیں

SHRI SUNIL BASU RAY (West Bengal): So, we are walking out.

(At this stage some hon. Members left the Chamber.)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो योजना है यह मजदूरों की बेरोजगारी की योजना है । इससे लाखों लाख मजदूर और कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे । दूसरा मेरा प्रोटेस्ट यह है कि यह 7 बजे का समय इस प्रकार के महत्वपूर्ण विषय को सदन में लाने का नहीं है । आप देख लीजिये, मुश्किल से 7–8 सदस्य यहां पर हैं । इसके विरोध में मैं सदन से बहिगमन करता हूं ।

(At ths stage the hon. Member left the Chamber.)

†‖] Transliteration in Arabic Script.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: *

श्री जगदीश प्रसाद माथुर :*

THE VICE-CHAIRMAN: (SHRI H. HANUMANTHAPPA): No, no, no. I am not permitting. Nothing will go on record.

एक तरफ तो आप शिकायत कर रहे हैं दूसरी तरफ से 8 बजे के बाद भी हाउस को चलाना चाहते हैं । आप सब बैठ जाइये । मैं यह कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो आप शिकायत करते हैं कि साढे 7 बजे तक हाउस को क्यों चला रहे हैं और दूसरी तरफ 8 बजे तक चलाना चाहते है। यह ठीक नहीं है ।

श्री अशोक गहलोत माननीय सदस्यों ने जो बात कही हैं और जो सुझाव दियेहै उनका मैं स्वागत करता हूं । मुझे इस बात का दुख है कि हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने बिना कोई बात सुने इस सदन से वाक-आउट कर दिया यह बहुत ही महत्वपूर्ण मसला था, उनको चहिए था कि बैठते , बातें करते, अपनी बात पूरी करते और उसके बाद उत्तर सुनने के बाद भी उनकी कोई शिकायत होती तो वे जा सकते थे । मुझे लगता है कि राजनैतिक तौर पर उन्होंने यह निर्णय किया है । पहले से ही सोच-समझ कर किया है । इसलिए मुझे कुछ कहना नहीं है क्योंकि यह एन० टी० सी० की बात नई नहीं है, सदन के सामने नई नहीं है और देश के सामने नई नहीं है । जब से नई सरकार बनी है-हमको मालूम है कि हर बार पार्लियामेंट के सेशनों के अन्दर लोक सभा में और राज्य सभा में यह सवाल उठा है । अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि तनख्वाह नहीं मिलती है, एन० टी० सी० की हालत बहुत खराब है, वहां घाटा हो रहा है । पूरे देश को मालूम है कि कितना भारी घाटा हो रहा है था ।

*Not recorded.

अगर प्रतिवर्ष 300 करोड़ रुपए की घाटे की स्थिति आ जाये, जैसे मैंने फिगर में बताया कि 2300 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है एन.टी.सी. को, तो यह एक चिंता वाली बात सारे देश के सामने है और मजदूरों के सामने भी है। मजदूर भी अब यह समझ गया है कि कैसे हम इन मिलों के चलाने में भागीदार बन पायेंगे। उनके सामने भी दिक्कत है। उनको आशंका है कि पता नहीं आने वाले वक्त में क्या होगा, हमें तनख्वाह मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि जो अर्थ-व्यवस्था अपने देश की बनी है, अर्थ-व्यवस्था जिस नाजुक दौर से गुजर रही है हमारे बैलेंस आफ पेमेंट की जो स्थिति है, उसके बारे में हमने कई घंटों तक सदन के अंदर बहस की है और हम सब को मालूम है कि सरकार के पास ताकत नहीं है जो वह इस घाटे को पूरा कर सके। मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि यू.पी. में कानपुर और यू.पी. की जो सब्सिडियेरी है एन.टी.सी. की, उसका अगर हिसाब लगाया जाये तो करीब साढ़े तीन, चार करोड़ पर मंथ बिना कुछ काम किये हुए हमें मजदूरों को वेतन के रूप में देना पड़ता है, क्योंकि वेतन देना बहुत आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मजदूर बेचारा कहां जायेगा। तो सारे हालात जो बने हुए थे, उनको देखते हुए हम लोगों ने तय किया, सरकार का निर्णय हुआ कि हम इस बारे में कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनायें, ऐसी रचना बनायें जिससे एन.टी.सी. की मिलें पुनर्जीवित हो सके, उनका पुनरुद्धार हो सके और वे मजबूत बन सकें। आज जो 1 लाख 76 हजार मजदूर वहां काम कर रहे हैं उनका भविष्य अंधकारमय बना हुआ है। अगर एन.टी.सी. की सारी मिलें बंद होती हैं तो जो ये 1 लाख 76 हजार लोग हैं, इनका भविष्य दांव पर है, यह सोचकर जो योजना बनायी गयी है वह इन मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाली है। मजदूर खुद तैयार बैठे हुए हैं कि वे वालेंटरी रिटायरमेंट लेकर अपना कोई दूसरा काम कर सकें। कुछ लोग पिछले तीन सालों में जा भी चुके हैं। यह कोई नयी योजना नहीं है। पिछले तीन सालों में करीब 17 हजार मजदूर वालेंटरी रिटायरमेंट लेकर जा चुके हैं। अभी हमारे पास सात हजार अप्लीकेशंस पेंडिंग पड़ी हुई हैं। यह दुर्भाग्य है कि मैं आपको बता रहा हूं कि एन.टी.सी. की स्थिति ऐसी बन गई है कि हम इन अप्लीकेशंस के आधार पर उनको जो पैसा देना चाहिए, वालेंटरी रिटायरमेंट के अन्तर्गत, वह पैसा भी एन.टी.सी. के पास नहीं है जिससे कि वे उनको वहां से हटा सकें। या स्वैच्छिक जो वे आप्शन लें, उसको पूरा कर सकें। यू.पी. के अंदर सहारनपुर में स्ट्राइक हुई। हमने किसी तरह वहां स्ट्राइक खुलवाई। मजदूर यूनियनों के साथ जो समझौता हुआ तो उसमें कुछ मजदूर वालेंटरी रिटायरमेंट में जाने के लिए खुद एग्री हो गये। लेकिन स्थिति ऐसी बनी है कि आज तक हम उन मजदूरों को बैठे हुए तनख्वाह दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास उनको देने के लिए पैसा नहीं था, जो कि करोड़ों में बनता था। वालेंटरी रिटायरमेंट में उनको पैसा नहीं दे सकते थे। आज हालत यह बन गई है कि कुछ मिलें ऐसी भी हैं, माननीय उपसभाध्यक्ष जी मैं कहना चाहूंगा कि जो किसी तरह ठीक नहीं हो सकती। जो आज से डेढ़ सौ साल पुरानी मिलें हैं, उससे भी अधिक साल पुरानी हैं, जिनकी मशीनें आब्सलेट हो चुकी हों, बिल्डिंग जर्जर हालत में है मुंबई में एक मिल की बिल्डिंग गिर गई, वहां एक हादसा हो सकता था। तो चारों ओर, हमारे माननीय सदस्य भी इस बात को जानते हैं कि वास्तव में यह कोई नई बात नहीं है। जिस तरह से एन.टी.सी. की हालत खराब बनी हुई है, इन सब बातों को देखते हुए हम लोगों ने जो योजना बनाई है, उसके अंतर्गत एक तो हम जिन मिलों को लेंगे उनका आधुनिकीकरण करेंगे। इस बारे में जो हमारे माननीय सदस्यों ने कहा हम कहना चाहेंगे कि हम उनका आधुनिक तरीके से आधुनिकीकरण करेंगे। हम चाहेंगे कि वहां पर अच्छे से अच्छा उत्पादन हो, अच्छी क्वालिटी का उत्पादन हो जिससे वह माल विदेशों में जा सके और हम एक्सपोर्ट कर सकें और वे मिलें अच्छे ढंग से चल सकें और मजदूरों को उसका लाभ मिल सके। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा

[श्री अशोक गहलोत]

कि जो स्कीम वी०आर०एस०, वालेंटरी रिटायरमेंट स्कीम, इसके अन्तर्गत हम कोई रिट्रेंचमेंट नहीं कर रहे हैं। यह उनके घर को बसाने वाली योजना है। जो अभी आपने सवाल उठाया मैं कहना चाहूंगा कि हमने ऐसी योजना नहीं बनायी है। हमने जो पहले योजना चल रही थी, उसमें नेशनल रेन्युअल फंड से जो पैसे आया है, उससे हमने प्राविजन लिया है कि कैसे उससे हम पैसे लेकर जो वालेंटरी रिटायरमेंट लेना चाहता है, इनको हम इसकी इजाजत दे सकें। इसके लिये योजना एक साल की नहीं है बल्कि तीन साल के पीरियड के अंदर जो लेबर जाना चाहे, इसमें अधिकारी भी हैं, इसमें कर्मचारी भी हैं और इसमें हमारे मजदूर भाई भी हैं। यह भी नहीं है कि खाली मजदूरों को भेजने वाली बात हम लोग कर रहे हैं बल्कि जो भी जाना चाहे वह इस स्कीम का लाभ उठाकर जा सकता है। इस तरह की जो हमने योजना बनाई है, इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इसमें आफिसर्स भी हैं, स्टाफ भी है, वरकर्स भी हैं, सभी लोग इसके अंदर हैं। हम चाहते हैं कि स्थिति इस प्रकार से बने कि उसमें आधुनिकीकरण भी हो और साथ ही साथ जो मजदूर जाना चाहे, जा सकें, अपना दूसरा काम कर सकें।

तीसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो मजदूर वी.आर.एस. के अन्तर्गत जाना चाहते हैं, हमने उनको भी कहा है कि अगर वे चाहें-हमने एक योजना पुनर्वास फंड स्थापित करके बनायी है, जिसका मैंने अपने स्टेटमेंट में जिक्र किया है, करीब 50 करोड़ रुपए की सहायता का-इसके अंतर्गत हम उनके लिये ट्रेनिंग का काम कर रहे हैं, उनको री-इम्पलाईमेंट के लिए स्कीम दे रहे हैं। हमने आर.बी.आई सारे बैंकों और सारी फाइनेंसियल इंस्टीट्यूशंस से टाई-अप कर लिया है।

हम चाहेंगे कि जो एन.टी.सी. के लूम्स सरप्लस हों और जो इस लायक हों वे लूम्स काम आ सकें। अगर पुराने लूम्स ले कर स्कीम में आना चाहेंगे तो उसके लिए अलग से स्कीम बनाई है। जो दो-चार लूम्स लेकर काम खुद करना चाहें अपना वे अपना काम कर सकते हैं। उनको जो बैंकों से लोन मिलने की बात है वह हम लोग दिलाने के लिए टाइ-अप करेंगे। 6 महीने तक अगर वह ढंग से काम करता है, वह लूम चला पाता है तो उसको खुद का जो कंट्रीब्यूशन होगा वह भी सरकार इस 50 करोड़ से वापस उसको देगी जिससे कि वह अपना काम खुद का, अपने परिवार का भी क्योंकि उसमें एक के अलावा तीन चार लोग और लग सकते हैं। इस प्रकार की योजनायें हैं जिसमें करीब 20 हजार मजदूर काम कर सकेंगे और 30-35 हजार दूसरे लोगों का काम मिल सकेगा। उसमें दूसरे मजदूर भी हो सकते हैं और दूसरे लोग भी उसमें काम आ सकते हैं। तो हमने यह योजना बनाई है। हमने यह योजना बनाई है कि अगर पुराने लोग नहीं बल्कि नये लोग लेना चाहें तो दो चार लूम्स नये ले सकते उसके लिए बड़ी योजना है। उसके लिए भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनको मदद देंगे। उसका खुद का कंट्रीब्यूशन होगा। उसमें हम देखेंगे कि नहीं वास्तव में यह काम कर रहा है, 6 महीने के बाद भी हम उसको वापस कम्पेनसेट करेंगे और चाहेंगे कि वह अपना काम निरंतर करता रहे।

तीसरा, मैंने देखा कि हैंक यार्न की बात है। माननीय सदस्य जैन साहब बैठे हैं, और सब लोग बराबर बोलते रहते हैं कि हैंक यार्न की कमी है या मिलता नहीं है। हमने तय किया है और इसमें डीलिंक की स्कीम बनाई है जिसके अंतर्गत जिन मजदूरों को अनुभव है वे मजदूर अगर हैंक यार्न बनाना चाहेंगे तो उनके लिए अलग से स्कीम बनाई है जिसमें काफी लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इस प्रकार से पूरी योजना बना करके हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर ऐसी स्थिति बने जिससे कि हम मजबूती के साथ एन.टी.सी. को चला सकें और एन.टी.सी. की पुनर्रचना इस प्रकार से हो सके, उनको पूरी मजदूरी मिल सके। यही सोच कर हमने इस योजना को अंतिम रूप दिया है। जो सरकार ने तय किया है वह मैंने सदन के सामने अपने वक्तव्य के रूप में बताया है।

इसी प्रकार बी.आई.सी., ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन की काटन की मिलें हैं कानपुर के अंदर। उनकी हालत भी कमोबेश इस तरह की है जिसके बारे में इस वक्तव्य के अंदर जिक्र किया है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो बातें हमने तय की हैं उससे हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में तीन साल के बाद में एन. टी.सी. में जो घाटे हैं वह ठीक हो सकेंगे और हम लोग कैश प्राफिट से शुरूआत कर सकेंगे। यही स्थिति बी.आई.सी की है जिसमें चौथे या पांचवें साल में इसमें भी कैश प्राफिट में हम लोग आ सकेंगे जिससे धीरे धीरे हम लोग ऐसी स्थिति में आ जायें, चाहें शो रूम की बात कही गई—माननीय सदस्यों ने कहा कि शो रूम में कपड़ा अच्छा नहीं मिलता है या पूरा नहीं मिलता है, शो रूम का जो किराया लगता है उससे भी कम उसका टर्न ओवर है, ये सब बातें आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, सदन के लोग कहते हैं और सब लोगों को मालूम है कि एन.टी.सी. एक सोशल आब्लीगेशन को पूरा करने के लिए बनाई गई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, सरकार के सामने आज भी यह मंशा है। उस सोशल आब्लीगेशन को सामने रखते हुए ही, मजदूरों के भविष्य की चिंता करते हुए भी आज 1 लाख 76 हजार मजदूर अगर एक साथ मिलें बंद हो जायें और घर बैठ जावें इससे अच्छा है कि जो स्वैच्छिक सेवा निवृत लेकर जाना चाहें वे लोग जायें बाकी लोग कम से कम बचते हैं वे तो कम से कम अपने उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं और सरकार भी चाहेगी कि धीरे-धीरे इन मिलों को मजबूती मिले। यही सोचकर सारे प्लान बनाये गये। यही बातें मुझे कहनी थीं। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA) I adjourn the House till 11 o' clock tomorrow.

The House then adjourned at forty-four minutes past seven of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 12th August, 1992.